

>

Title: Need to deploy 'Fire Watcher' and 'Guards' for safety of forests and crops in Himachal Pradesh under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme.

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिक्षा): मैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी शर्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की शूली में वनों से रक्षा के लिए "फायर वार्टर" एवं किसानों की फसलों की जंगली जानवरों से रक्षा के लिए रखवाले नियुक्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। मैं सदन को अवगत करना चाहता हूं कि पहाड़ी क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में गर्मियों में कई बार वनों में अकरमात् अर्यांकर आग लग जाती है जिससे अरबों रुपए की वन सम्पदा एवं जीवनरक्षक जड़ी-बूटियाँ तथा दुर्तम् प्रजाति के जंगली जानवर भरम हो जाते हैं, लेकिन आग बुझाने अथवा उस पर काबू पालेके लिए वन विभाग के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं तथा रथानीय तोग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद जंगलों को बताने में सहयोग इसलिए नहीं करते हैं, व्योंकि उन्हें जंगल लगाने का तो अधिकार है, लेकिन उन जंगलों से ताम उठाने पर योक है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की फसलों को जंगली जानवर तबाह कर देते हैं, लेकिन उनसे रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, व्योंकि जंगली जानवरों को मारने पर कानूनी योक है। अतः हिमाचल प्रदेश में आग से वनों को बताने के लिए "फायर वार्टर" तथा किसानों की फसलों को बताने के "रखवाले" नियुक्त करने का प्रावधान मनमेणा योजना में किए जाने का अनुरोध है।

-